रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्रपद 7, 1930
No. 470] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRAPADA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 622(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1 लघु नाम और प्रारम्भ:-

(1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 कहा जाएगा ।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 2006 से लागू माना जाएगा ।

2 उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये निर्णय लागू होंगे:-

(1) अन्यथा उपलब्ध व्यवस्था या इन नियमों में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में नियुक्त कर्मचारियों और पदों, जिनका वेतन सिविल प्राक्कलन में से अदा होता है तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

(2) . ये नियम लागू नहीं होंगे:-

(i) उन व्यक्तियों पर, जो केन्द्रीय सिविल सेवाओं और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में नियुक्त हैं ।

(ii) उन व्यक्तियों पर, जो राजनयिक, कांसुली अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानीय रूप से सेवार्थ भर्ती हैं;

(iii) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवायोजन में नहीं हैं;

(iv) उन व्यक्तियों पर, जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है;

(v) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है;

(vi) उन व्यक्तियों पर जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं । केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां अनुबंध में अन्य प्रकार से इसका प्रावधान किया गया हो;

नोट 1- जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा सेवा-मुक्ति अथवा अनुशासनहीनता के कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी इस नियम के लाभों का अधिकार होगा ।

नोट 2- जो लोग 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अंदर संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों को लाभप्रद लगे, उन्होंने नए वेतनमान का चयन कर लिया है । अगर संशोधित वेतन ढाँचे उनके हक में हैं तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी ।

नोट 3- जो व्यक्ति 1/1/2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी के हकदार बनाता है, उन्हें छुट्टी के इस नियम के लाभ मिलेंगे ।

7 संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण:

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसने 1 जनवरी, 2006 को और उसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के उप नियम (3) के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह कार्य-पुनर्ग्रहणाधिकार रखता है या निलंबित न होने की स्थिति में यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष नियम या अन्यथा निर्देश ना हो, उसका आरंभिक वेतन अलग से निर्धारित किया जाएगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा ।

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में-

(i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1/1/2006 को यथाविद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा ।

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि:-

वेतन निर्धारण में जहां कहीं सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है, अर्थात अन्यथा कहें तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके । इस प्रयोजन के लिए वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी । बंचिंग को कम करने के लिए वेतनवृद्धियां देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

(ख) ऐसे मौजूदा समूह "घ" कर्मचारी, जो पी.बी.1 में प्रविष्टि के लिए संशोधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, को संबंधित विभाग द्वारा अधिमानत: छह माह के भीतर पुन: प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि स्तरोन्नयन के फलस्वरूप मिलने वाले बकाया के भुगतान में विलम्ब न हो । पुन: प्रशिक्षण के बाद इन समूह "घ" कर्मचारियों को भी 1.1.2006 से 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी.बी.1 में रखा जाएगा और तदनुसार बकाया राशि आहरित की जाएगी । एक बार वेतन बैंड पी.बी.1 में आने के बाद, इस श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारी पहले से ही न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अन्य श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारियों की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुन: प्राप्त कर लेगें और इसीलिए ये 1.1.2006 को पी.बी. वेतन बैंड में रखे गए हैं । तत्कालीन समूह "घ" में सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निचले वेतनमान वाले कर्मचारी की तुलना में उच्च वेतनमान में रखे जा रहे पूर्व-संशोधित उच्च वेतनमान वाले समूह "घ" कर्मचारी के साथ पूरी तरह बहाल रखी जाएगी । उसी पूर्व-संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता, जो संशोधन से पहले थी, बनी रहेगी ।

(ग) दोनों मामलों में अर्थात अर्हताएं रखने वाले समूह "घ " के वे कर्मचारी जिन्हें सीधे पी.बी.1 में रखा गया है तथा समूह "घ" के वे कर्मचारी जिनके पास अर्हता नहीं है, लेकिन पुन: प्रशिक्षण के बाद रखा गया है, की बकाया राशि 1.1.2006 से देय होगी । समूह "घ" कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित उदाहरण 3 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

टिप्पणी 2क- जहां किसी पद को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें के फलस्वरूप स्तरोन्नत किया गया है, जैसा कि इन नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग "ख" अथवा भाग **"ग"** में दर्शाया गया है, वहाँ लागू वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुरूप निर्धारित पद्धति से दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन को गुणक 1.86 से गुणा करने के फलस्वरूप आने वाली संख्या को दस के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा । स्तरोन्नत वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, जैसा भाग "ख" अथवा "ग" के कॉलम 6 में दर्शाया गया है, अतिरिक्त रूप से देय होगा । इस संबंध में ***उदाहरण 4 क*** इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

टिप्पणी 2(ख)- वेतनमानों के आमेलन के मामले में, संशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन दिनांक 01.01.2006 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार मौजूद मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त संख्या को दस के गुणक में पूर्णांकित करते हुए नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुसरण में निर्धारित तरीके से मौजूद मूल वेतन को गुणा करते हुए किया जाएगा । भाग ख अथवा ग के कॉलम 6 में दर्शाए गए अनुसार आमेलित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन इसके अतिरिक्त दिया जाएगा । इस संबंध में इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में ***उदाहरण 4 ख*** दिया गया है ।

टिप्पणी 3- यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो और वह छुट्टी का वेतन लेने का हकदार हो तो वह 1.1.2006 से अथवा संशोधित वेतन ढांचें में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा । इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को अध्ययनार्थ छुट्टी पर हो तो वह 1.1.2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा ।

टिप्पणी 4- निलंबित सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा ।

टिप्पणी 5- जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किस उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाए जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जाएगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2008

G.S.R. 622 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules, namely : -

1. *Short title and commencement* -

(1) These rules may be called the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. *Categories of Government servants to whom the rules apply*: -

(1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union whose pay is debitable to the Civil Estimates as also to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department.

(2) These rules shall not apply to : -

(i) persons appointed to the Central Civil Services and posts in Groups 'A', 'B', 'C' and 'D' under the administrative control of the Administrator of the Union Territory of Chandigarh;

(ii) persons locally recruited for service in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;

(iii) persons not in whole-time employment;

(iv) persons paid out of contingencies;

(v) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;

(vi) persons employed on contract except where the contract provides otherwise;

(vii) persons re-employed in Government service after retirement;

made subsequent to that date, within three months of the date of such order.

Provided that -

(i) in the case of a Government servant who is, on the date of such publication or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and

(ii) where a Government servant is under suspension on the 1st day of January, 2006 , the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.

(2) The option shall be intimated by the Government servant to the Head of his Office.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect on and from the 1st day of January, 2006.

(4) The option once exercised shall be final.

Note 1 - Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge or disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note 2 - Persons who have died on or after the 1st day of January, 2006 and could not exercise the option within the prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006 or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office.

Note 3 - Persons who were on earned leave or any other leave on 1.1.2006 which entitled them to leave salary will be allowed the benefits of this rule.

7. ***Fixation of initial pay in the revised pay structure:***

(1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect

of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely :-

(A) in the case of all employees:-

(i) the pay in the pay band/pay scale will be determined by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10.

(ii) if the minimum of the revised pay band/ pay scale is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band/pay scale;

Provided further that:-

Where, in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, the increment will be calculated on the pay in the pay band. Grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increments to alleviate bunching.

In the case of pay scales in higher administrative grade (HAG) in the pay band PB-4, benefit of increments due to bunching shall be given taking into account all the stages in different pay scales in this grade. In the case of HAG+ scale, benefit of one increment for every two stages in the pre-revised scale will be granted in the revised pay scale.

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised pay band/ pay scale (where applicable) which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a Government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former.

(iii) The pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable.

Note - ***Illustration 1*** on the above is provided in the Explanatory Memorandum to these Rules.

(B) In the case of employees who are in receipt of special pay/allowance in addition to pay in the existing scale which has been recommended for replacement by a pay band and grade pay without any special pay/allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of clause (A) above.

fixation of pay for Group D staff is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

Note 2A - Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Sixth CPC as indicated in Part B or Part C of the First Schedule to these Rules, the fixation of pay in the applicable pay band will be done in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the upgraded scale as indicated in Column 6 of Part B or C will be payable in addition. ***Illustration 4A*** in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

Note 2B - In the case of merger of pay scales, pay in the revised pay bands will be fixed in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the merged scale as indicated in Column 6 of Part B or C will be payable in addition. ***Illustration 4B*** in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

Note 3 - A Government servant who is on leave on the 1st day of January, 2006 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2006 or the date of option for the revised pay structure. Similarly, where a government servant is on study leave on the first day of January, 2006 he will be entitled to the benefits under these Rules from 1.1.2006 or the date of option.

Note 4 - A Government servant under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised pay structure will be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

Note 5 - Where a Government servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the officiating post only, and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.

The provisions of this Note shall apply mutatis mutandis, to Government servants holding in an officiating capacity, posts on different existing scales which have been replaced by the revised pay structure.

Note 6 - Where the `existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 7 - Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 2006 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower

33	S-31	22400-600-26000	HAG+ Scale	75500- (annual increment @ 3%) -80000	Nil
34	S-32	24050-650-26000	HAG+ Scale	75500- (annual increment @ 3%) -80000	Nil
35	S-33	26000 (Fixed)	Apex Scale	80000 (Fixed)	Nil
36	S-34	30000 (Fixed)	Cab. Sec.	90000 (Fixed)	Nil

Section II

Entry Pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1.1.2006

PB-1 (Rs.5200-20200)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

PB-2 (Rs.9300-34800)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

PB-3 (Rs.15600-39100)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

PB-4 (Rs.37400-67000)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.1800
8.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.7330

Illustration 4A : Pay fixation in cases where posts have been upgraded e.g. posts in pre-revised pay scale of Rs.3050-75-3950-80-4590 to Rs.3200—85-4900 scale

1.	Existing Scale of Pay	Rs.3050-4590 (Corresponding Grade Pay Rs.1900)
2.	Pay Band applicable	PB-1 Rs.5200-20200
3.	Upgraded to the Scale of Pay	Rs.3200-4900 (Corresponding Grade Pay Rs.2000)
4.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.3125
5.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs.5813 (Rounded off to Rs.5820)
6.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.5820
7.	Pay in the pay band after including benefit of bunching in the pre-revised scale of Rs.3050-4590, if admissible	Rs.6060
8.	Grade Pay attached to the scale of Rs.3200-4900	Rs.2000
9.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.8060

Illustration 4B : Pay fixation in cases where pay scales have been merged e.g. pre-revised pay scales of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500

1.	Existing Scale of Pay	Rs.5000-150-8000
2.	Pay Band applicable	PB-2 Rs.9300-34800
3.	Merged with the scale of pay	Rs.6500-200-10500
4.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.5600
5.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs. 10416 (Rounded off to Rs.10420)
6.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.10420
7.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs.10420